सामने रखता है।

3. यह सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' का रोडमैप है।

यह अभिभाषण हमें बताता है कि कैसे 2014 के बाद से भारत का हर नागरिक एक भागीदार बन गया है, कैसे नीतियों से योजनाएँ बनीं और योजनाओं से उपलब्धियाँ मिलीं।

निष्कर्ष - एक नए भारत की ओर

- यह भारत अब केवल भविष्य के सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है।
- यह भारत एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल एक आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक संकल्प है-एक सुनहरे भारत का संकल्प।

इसलिए, मैं इस ऐतिहासिक अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करती हूँ और इस सदन से अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर इस महान राष्ट्र के विकास में योगदान दें।

जय हिंद! वंदे मातरम

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के संबोधन पर आभार प्रकट करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कल और आज, कल तो रात देर तक सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए। यह स्वाभाविक है और लोकतंत्र की परम्परा भी है, जहां आवश्यकता थी, वहां प्रशंसा हुई और जहां परेशानी थी, वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई। यह स्वाभाविक भी है।

अध्यक्ष जी, मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे चौदहवीं बार इस जगह से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसलिए, मैं आज जनता-जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सदन में चर्चा में जिन-जिन लोगों ने हिस्सा लिया और चर्चा को समृद्ध किया, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम वर्ष 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25 परसेंट हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा कि 20वीं सदी में आजादी मिलने के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25

साल में क्या हुआ, कैसा हुआ? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हम बारीकी से अध्ययन करें तो यह साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात कही है। एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का यह उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन-सामान्य को प्रेरित करने वाला है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे अध्ययन बार-बार यह कह चुके हैं कि गत दस वर्षों में देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया, उसमें 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर आ चुके हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, लोगों ने पांच-पांच दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने होंगे और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले हैं, यह ऐसे ही नहीं हुआ है।

योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ, जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं न, तब यह होता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब जमीन से जुड़े लोग, जमीन की सच्चाई को जानते हुए, जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होकर रहता है। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके लिए जज्बा चाहिए और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में यह है ही नहीं। बारिश के दिनों में कच्ची छत, उसकी प्लास्टिक की चादर वाली छत, उसके नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल-पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं। यह हर कोई नहीं समझ सकता।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब तक गरीबों को चार करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है। एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वह या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों

को झेलने के बाद, यह छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों और बेटियों की मुश्किलें दूर की हैं। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूज़ी पर, स्टाइलिश शॉवर्स पर है, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है।

आजादी के 75 सालों के बाद देश में 75 प्रतिशत करीब-करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों में जल के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 सालों में 12 करोड़ परिवारों के घरों में नल से जल देने का काम किया है और यह काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान करके छूट नहीं सकते हैं। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 सालों के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा, हमारा प्रयास समस्या के समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांवों में 15 पैसे पहुंचते हैं। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एक रुपया निकलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। 15 पैसे किसके पास जाते

थे, यह देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने हमें अवसर दिया। हमने समाधान खोजने का प्रयास किया।

हमारा मॉडल है – बचत भी, विकास भी, जनता का पैसा जनता के लिए। ... (व्यवधान) हमने जनधन, आधार, मोबाइल - जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना शुरू किया। हमने अपने कार्यकाल में 40 लाख करोड़ रुपये सीधा जनता-जनार्दन के खाते में जमा किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गईं? किसके लिए चलाई गईं? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन की गरिमा बनाए रखें। कोई माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करेगा। यह उचित नहीं है। आपका यह गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन की मर्यादा नहीं है। आप उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? यह गलत तरीका है। आप बैठे-बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जब ज्यादा हताशा और निराशा फैल जाती है, तब भी बहुत कुछ बोलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे दस करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग-अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सही के साथ अन्याय न हो, इसलिए राजनीति फायदा-नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन दस करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज-खोज कर उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दस करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न-भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाया तो करीब तीन लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था, यह नहीं

कह रहा हूं, गलत हाथों से बच गए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने सरकारी खरीद में भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। हम ट्रांसपेरेंसी लाए और जेम पोर्टल, जिसका आज राज्य सरकारें भी उपयोग कर रही हैं, से जो खरीदी हुई, आम तौर पर जो खरीदी होती है, उससे कम पैसे में खरीदी हुई और सरकार की 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया। ऐसे जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, न जाने क्या-क्या कहा जाता था। … (व्यवधान) लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इस सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया न, उसमें 2 हजार 300 करोड़ रुपये सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वे कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं। ये सम्पत्ति जनता-जनार्दन की है और इसीलिए हम पाई-पाई को इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह में उपयोग करने का प्रयास करते हैं और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेच कर 2 हजार 300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया इथेनॉल ब्लैंडिंग का। हम जानते हैं कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें बाहर से लाना पड़ता है। जब इथेनॉल ब्लैंडिंग किया है और हमारे पेट्रोल, डीजल की आय कम हुई, तो उस एक निर्णय से 1 लाख करोड़ रुपये का फर्क पड़ा है। यह पैसे, करीब-करीब 1 लाख करोड़ रुपये किसानों की जेब में गये हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हैडलाइन हुआ करती थी कि इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों-करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता-जनार्दन की सेवा में लगे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये जो अलग-अलग कदम उठाये हैं, उससे लाखों-करोड़ रुपये की बचत हुई है। लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया है। इसका उपयोग

हमने देश बनाने के लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट दस साल पहले एक लाख 80 हजार करोड़ था, हमारे आने से पहले, आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने भारत की नींव कैसे मजबूत हो रही है, इसका वर्णन इसमें किया है। रोड हो, हाइवे हो, रेलवे हो, ग्राम सड़क हो, इन सभी कामों के लिए विकास की एक मजबूत नींव रखी गई है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी खजाने में बचत हुई, वह तो एक बात है और वह करना भी चाहिए। जैसे मैंने ट्रस्टीशिप की बात कही है। लेकिन हमने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि जनसामान्य के, उनको भी इस बचत का लाभ मिलना चाहिए। योजनाएं ऐसी हों, ताकि जनता को भी बचत हो और आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत योजना में बीमारी के कारण सामान्य मानवी का जो खर्च होता था, अब तक जिन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, उसी के हिसाब से मैं कहता हूं कि करीब-करीब देशवासियों का, आयुष्मान योजना का बेनिफिट लेने के कारण जो खर्चा उनको अपनी जेब से करना पड़ता, वैसे 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये जनता-जनार्दन के बचे हैं।

यह आवश्यक है। जैसे जन औषधि केन्द्र हैं, आज मध्यमवर्गीय परिवारों में 60 से 70 वर्ष के स्वजन हों, तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। उसमें दवाई का खर्चा भी होता है। दवाएं महँगी भी होती हैं। जब से हमने जन औषधि केन्द्र खोले हैं, जिसमें 80 परसेंट डिस्काउंट होता है, उसके कारण जिन परिवारों ने इन जन औषधि केन्द्रों से दवाइयाँ ली हैं, उनके लगभग 30 हजार करोड़ रुपए दवाइयों के खर्च बचे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यूनिसेफ का भी अनुमान है, उनका कहना है कि जिसके घर में स्वच्छता है और टॉयलेट बना हुआ है, उन्होंने इसके बारे में एक सर्वे किया था, उस परिवार को साल भर में लगभग 70 हजार रुपए की बचत हुई है। स्वच्छता अभियान कहो, टॉयलेट बनाने का काम कहो, शुद्ध जल पहुंचाने का काम कहो, इनसे कितना बड़ा फायदा सामान्य परिवारों को हो रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, नल से जल योजना, जिसका उल्लेख मैंने प्रारम्भ में किया। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आयी है। उसका कहना है कि 'नल से जल योजना' के तहत शुद्ध पानी मिलने के कारण उन परिवारों में, जो अन्य बीमारियों के खर्चे होते थे, इससे परिवार के औसतन 40

हजार रुपए बचे हैं। मैं ज्यादा नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिसने एक सामान्य मानवी के खर्च में बचत की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, करोड़ों देशवासियों को मुफ्त अनाज मिलते हैं। उन परिवारों के भी हजारों रुपए बचते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जहाँ-जहाँ लागू हुई है, वहाँ परिवारों को साल भर में, औसतन 25 से 30 हजार रुपए बिजली के खर्च में बचत हो रही है। अगर ज्यादा बिजली होती है, तो उसको बेचकर कमाई कर रहा है, वह अलग है। यानी इसके द्वारा सामान्य मानवी की बचत भी हो रही है। हमने एलईडी बल्ब का एक अभियान चलाया था। आपको मालूम है कि हमारे आने के पहले एलईडी बल्ब 400 रुपए में बिकते थे। हमने इसका इतना अभियान चलाया कि उसकी कीमत 40 रुपए हो गई। एलईडी बल्ब के कारण बिजली की भी बचत हुई और इससे उजाला भी ज्यादा मिला। इससे देशवासियों के करीब 20 हजार करोड़ रुपए बचे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया, उनको बहुत फायदा हुआ है। ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 30 हजार रुपए की बचत हुई है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 10 साल में, इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है।

वर्ष 2014 के पहले ऐसे बम-गोले फेंके गए, बन्दूक की ऐसी गोलियाँ चलाई गईं कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हम धीरे-धीरे उन घावों को भरते-भरते आगे बढ़े हैं। वर्ष 2013-14 में सिर्फ 2 लाख रुपए पर इनकम टैक्स माफी थी और आज 12 लाख रुपए पर संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति दी गई। हम बीच के कालखंड में भी, वर्ष 2014 में भी, वर्ष 2017 में भी, वर्ष 2019 में भी और वर्ष 2023 में भी लगातार यह करते आए। घाव भरते गए और आज जो बैंडेज बाकी था, वह भी कर लिया। ... (व्यवधान) स्टैन्डर्ड डिडक्शन के अगर 75,000 रुपए जोड़ दें, तो पहली अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास है, उनको पौने तेरह लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे, तब एक बात आप सुनते

होंगे, पढ़ते भी होंगे। एक प्रधान मंत्री आए दिन 21वीं सदी, 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था। वे 21वीं सदी, 21वीं सदी बोलते थे। जब इतनी बार बोला जाता था, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर. के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वह कार्टून बड़ा इंट्रेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है, अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया, वह तो मुझे नहीं मालूम है। कुछ पैसेंजर्स बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पर रखा हुआ था। मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वह कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चलकर वह सच सिद्ध हो गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह कटाक्ष था। जमीनी सच्चाई से तब के प्रधान मंत्री कितने कटे हुए थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वह जीता-जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थीं, वे 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं देखता हूं, पिछले दस सालों से सारे विषयों को बारीकी से देखने का अवसर मिला है, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। हम 40-50 साल लेट हैं। जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए थे और इसलिए जब वर्ष 2014 से देश की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया। … (व्यवधान) हमने युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया। … (व्यवधान) हमने युवाओं के लिए ज्यादा अवसर बनाए। … (व्यवधान) हमने कई क्षेत्रों को खोल दिया, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि देश के युवा अपने सामर्थ्य का परचम लहरा रहे हैं। … (व्यवधान)

देश में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया, डिफेंस सेक्टर को खोला, हम सेमीकंडक्टर मिशन लेकर आए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाओं को हमने आकार दिया। स्टार्ट अप इंडिया के लिए पूरा इको सिस्टम डेवलप किया और इस बजट में भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स की माफी, यह समाचार इतना बड़ा बन गया कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमने

न्युक्लियर एनर्जी सैक्टर को ओपन कर दिया है। इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, थ्रीडी प्रिन्टिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रिएलिटी की चर्चा, हम तो गेमिंग का भी महात्मय क्या होता है, इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से हैं। मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया की गेमिंग क्रिएशन की क्रिएटिविटी, वर्ल्ड की कैपिटल भारत क्यों न बने और मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, अब जब एआई की बात होती है, यह शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई है। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया है। हमने स्कूलों में 10 हजार टिंकरिंग लैब्स शुरु की हैं और आज उन टिंकरिंग लैब्स से निकले हुए बच्चे रोबोटिक्स बनाकर लोगों को चकित कर रहे हैं। इस बजट में 50 हजार नए टिंकरिंग लैब्स का प्रावधान किया गया है। भारत वह देश है, जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफार्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस साल बजट में हमने डीप टेक के डोमेन में इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं समझता हूँ कि डीप टेक हमारे लिए तेज गति से आगे बढ़ने के लिए और 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सेंचुरी है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि भारत डीप टेक के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान कि ये भत्ता देंगे, वह भत्ता देंगे, वायदा तो करते हैं, लेकिन वायदा पूरा नहीं करते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखें। आप भारत की संसद में हैं। प्लीज बैठे-बैठे टिप्पणी न करें। नए माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। हम कैसे काम करते हैं, यह हरियाणा में अभी-अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वायदा किया था। सरकार बनते ही नौजवानों को नौकरी मिल गई। हम जो कहते हैं, उसी का परिणाम है। हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय प्राप्त हुई है और हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार विजय अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें मिलना जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पहली बार करके आए हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको समझना चाहिए, कल आपको जवाब दिया था।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे संविधान के 75 वर्ष होने पर भी विस्तार से चर्चा की है। संविधान में जो धाराएं हैं, उनके साथ-साथ संविधान का एक स्पिरिट भी है और संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। मैं आज उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते हैं। यह बात सही है कि हमारे यहां परम्परा है कि राष्ट्रपति जी जब उद्बोधन करते हैं तो उस सरकार के उस साल के कार्यकलाप का ब्यौरा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर का सदन में जो उद्बोधन होता है, उसमें राज्य के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान और लोकतंत्र की स्पिरिट क्या होती है। जब गुजरात के 50 साल हुए और गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे, उस समय सौभाग्य से मैं मुख्य मंत्री के रूप में सेवारत था। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने गोल्डन जुबली ईयर में पिछले 50 वर्षों में सदन में जितने भी भाषण गवर्नर ने दिए, मतलब उस समय की सरकारों की वाहवाही ही उन भाषणों में होती है, हमने कहा कि 50 सालों में गवर्नर के जितने भी भाषण हुए हैं, उन सभी को एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए, ग्रंथ बनाया जाए और आज सभी लाइब्रेरीज में वह ग्रंथ एवेलेबल है।

मैं तो बी.जे.पी. वाला था, गुजरात में तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही थीं, उन सरकारों के गवर्नर्स के भाषण थे। लेकिन उसको भी प्रसिद्ध कराने का काम भा.ज.पा. से बना एक मुख्य मंत्री कर रहा था। क्यों? क्योंकि हम संविधान को जीना जानते हैं। हम संविधान को समर्पित हैं। हम संविधान के स्पिरिट को समझते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में जब हम आए तो मान्य विपक्ष नहीं था, रेकग्निाइज्ड ऑपोजीशन पार्टी नहीं थी। उतने अंक भी लेकर कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि उस कानून के हिसाब से काम करने की हमें पूरी स्वतंत्रता थी। अनेक कमेटियां ऐसी थीं, जिनमें लिखा था कि 'लीडर ऑफ ऑपोजीशन' उसमें आएंगे। लेकिन, ऑपोजीशन था ही नहीं, रेकग्निाइज्ड ऑपोजीशन नहीं था। यह हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, यह हमारा संविधान का स्पिरिट था, यह हमारा लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले ही मान्य विपक्ष नहीं होगा, रेकग्निाइज्ड ऑपोजीशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, उनको मीटिंग्स में बुलाएंगे।… (व्यवधान) यह लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है।… (व्यवधान) चुनाव आयुक्त से संबंधित कमेटियां थीं।… (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधान मंत्री फाइल पर साइन करके निकालते थे। यह हम हैं, जिसने ऑपोजीशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। हमने इसके लिए कानून भी बनाया और आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो ऑपोजीशन लीडर भी उसके निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। यह काम हम करते हैं।… (व्यवधान) मैंने पहले ही कहा कि हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि हम संविधान को जीते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बनाकर रखे हुए हैं। जनता-जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं? हमने पी.एम. म्यूजियम बनाया। देश के पहले से लेकर मेरे से पूर्व तक के सभी प्रधान मंत्रियों के जीवन को और उनके कार्यों को दर्शाने के लिए वह पी.एम. म्यूजियम बनाया गया है। मैं तो चाहूंगा कि इस पी.एम. म्यूजियम में जो-जो महापुरुष हैं, उनके परिवारजनों

को समय निकाल करके उस म्यूजियम को देखना चाहिए और अगर उन्हें उसमें कुछ जोड़ने के लिए लगता है तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि वह म्यूजियम समृद्ध हों और देश के बालकों को प्रेरणा दे। यह होती है संविधान की भावना। अपने लिए तो सब करते हैं। खुद के लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम संविधान की भावना को लेकर चलते हैं। हम 'जहर की राजनीति' नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू, दुनिया का सबसे ऊँचा स्टैच्यू 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाते हैं। जिस महापुरुष ने देश को जोड़ने का काम किया, उनका हम स्मरण करते हैं। वे भा.ज.पा. के नहीं थे, वे जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह देश का दुर्भाग्य है कि आज-कल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुले आम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, यह अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सात दशक तक जम्मू-कश्मीर एण्ड लद्दाख को संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। यह संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल-370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वही अधिकार उनको मिल रहे हैं। संविधान का माहात्म्य हम जानते हैं। हम संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे निर्णय भी हम करते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में ले कर जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मज़बूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर के संविधान की भावना के

अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही है, हमने एक लंबे विज़न के साथ काम किया है।

पता नहीं देश को बांटने के लिए किस-किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हताशा, निराशा पता नहीं उनको कहां तक ले जाएगी। लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथी मिल कर के किस दिशा में सोचते हैं, हमारे लिए जो पीछे है, जो आखिरी है और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। उसी का परिणाम है कि अगर हम मंत्रालयों की रचना करते हैं, तो भी मंत्रालय कौन सा बनाते हैं? पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। इतने साल हो गए, अटल जी आए, तब तक किसी को समझ नहीं आया था। भाषण तो देते रहते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय एनडीए ने बनाया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिण के राज्य, समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्व के कई राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। वहां के समाज में फिशरीज़ का काम और फिशरमैन की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। उनका भी ख्याल रखना चाहिए।

18.00 hrs

जमीन के भीतर पानी के जो छोटे इलाके होते हैं, वहां भी फिशरमैन के रूप में काम करने वाले समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। यह हमारी सरकार है, जिन्होंने फिशरिज के लिए अलग मंत्रालय बनाया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय प्रधानमंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र मोदी: आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज के दबे, कुचले, वंचित लोगों के अंदर एक सामर्थ्य होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाए तो उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं। हम उनकी आशा व आकांक्षा के अनुरुप जिंदगी बना सकते हैं। इसलिए, हमने अलग से स्किल मंत्रालय बनाया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश में लोकतंत्र का पहला धर्म होता है कि हम सत्ता को सामान्य से सामान्य नागरिक तक उसका अवसर मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को और समृद्ध बनाने के लिए, और तंदुरुस्त बनाने के लिए देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए उसमें अवसर है। अनेक क्षेत्रों में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। विजन क्या होता है, यह यहां पता चलता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है। पिछले तीस साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। हम हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे देशवासी जरूर इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताए कि क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के तीन सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के तीन सांसद कभी भी हुए हैं क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के तीन एमपी हुए हैं क्या?

आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है? मेरे एक सवाल के जवाब में यह मिल जाएगा।…(व्यवधान) जमीन-आसमान का अन्तर होता है, रात-दिन का अन्तर होता है।…(व्यवधान) हम एससी, एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं, समाज में तनाव पैदा किए बिना, एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है,

इसका मैं एक उदाहरण देता हूं।…(व्यवधान)

वर्ष 2014 के पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं तो सीटें भी बढ़ी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण एंगल है।…(व्यवधान) कॉलेज भी बढ़े हैं, सीटें भी बढ़ी हैं।…(व्यवधान) वर्ष 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की 7,700 सीट्स थीं। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवाओं के डॉक्टर बनने की सम्भावना थी। हमने दस साल काम किया।…(व्यवधान) आज संख्या बढ़कर, एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर्स की व्यवस्था की है। …(व्यवधान) कहां 7,700 और कहां 17,000? समाज में तनाव लाए बिना, एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए यह किया। …(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। वर्ष 2014 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम सीटें थीं। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दस सालों में हर सप्ताह एक नई यूनीवर्सिटी बनी है, हर दिन एक नई आईटीआई बनी है, हर दो दिन में एक नया कॉलेज खुला है। सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे युवा-युवतियों के लिए कितनी वृद्धि हुई है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर योजना के पीछे लगे हैं, सौ प्रतिशत सेचुरेशन, शत प्रतिशत उसको लागू करें, उसके जो भी लाभार्थी हैं, उसमें वह छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है और उसका हक है तो उस तक पहुंचना चाहिए। एक रुपये और पन्द्रह पैसा वाला खेल नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ, तुष्टिकरण की राजनीति करो। देश को विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टिकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने संतुष्टिकरण का रास्ता चुना है। तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण, हम उस रास्ते पर चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के उसका हक मिलना चाहिए, यह है संतुष्टिकरण। मेरे हिसाब से जब मैं हंड्रेड परसेंट

सेचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि असल में सामाजिक न्याय है, यह असल में सेकुलरिज्म है और असल में संविधान का सम्मान है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान की भावना है, सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, आज कैंसर डे भी है। दुनिया और देशभर में हेल्थ को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। कुछ लोग हैं, गरीब और बुजुर्गों को आरोग्य की सेवा मिले, उसमें वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अड़गें डाल रहे हैं। आज आयुष्मान से देश के तीस हजार अस्पताल जुड़े हैं, अच्छे स्पेशलाइज्ड प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं। जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त में इलाज मिलता है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे थे। इसका नुकसान कैंसर के मरीजों को उठाना पड़ा है। पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ जर्नल लैन्सेट की स्टडी में आया, उसका कहना है कि आयुष्यमान योजना से समय पर कैंसर का इलाज शुरू हो रहा है। सरकार कैंसर की जांच कराने के संबंध में बहुत ही गंभीर है, जितना जल्दी जांच हो, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो तो हम कैंसर पेशेंट को बचा सकते हैं। लैन्सेट से आयुष्मान योजना को क्रेडिट देते हुए कहा है कि भारत में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में कैंसर की दवाइयों को सस्ता करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज कैंसर डे हैं, मैं सभी माननीय सांसदों से कहना चाहूंगा कि अपने इलाके के ऐसे मरीजों के लिए आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप जानते हैं, मरीजों के लिए उतने अस्पताल नहीं होने के कारण बाहर से आने वाले पेशेंट को काफी दिक्कतें होती हैं। दो सौ डे केयर सेंटर बनाने का निर्णय इस बजट में किया गया है। डे केयर सेंटर पेशेंट ने पेशेंट और उसके परिवार को बहुत बड़ी राहत देने का काम करेगा।

आरदणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई।

कुछ लोगों को लगता है कि जब तब वे फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं बोलते हैं, तब तक वे मैच्योर नहीं लगते हैं। उनको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलना चाहिए, भले ही देश का नुकसान हो

जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है, फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर कुछ करना भी है, यह मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि वे एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उससे उनको कहां क्या बोलना है, उतनी समझ हो जाएगी। उस किताब का नाम 'जेएफकेज फॉरगोटेन क्राइसिस' है। उसमें जे.एफ कैनेडी की बात है। 'जेएफकेज फॉरगोटेन क्राइसिस' नाम की एक किताब है। यह किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है। उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, वे विदेश नीति का भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ.कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का विस्तार से वर्णन है। … (व्यवधान) जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से अब सामने आ रहा है। इसलिए, मैं कहूंगा कि ये किताब पढ़िए। … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या-क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति में हताशा-निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा व्यवहार करने का क्या कारण है? … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता छोड़कर के, उस सोच को छोड़कर के, वीमेन-लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी को उसको पूरा अवसर मिले तो भारत दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। यह मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद हमारा विश्वास और दृढ़ हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले दस साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से अब तक दस करोड़ नई महिलाएं एसएचजीज में जुड़ी हैं। वे महिलाएं वंचित परिवारों से और ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं।

समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर पर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20,00,000 रुपये तक बढ़ा दी है, ताकि वे इस काम को आगे बढ़ा सकें। उनकी कार्य क्षमता बढ़े, उनका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में 'लखपति दीदी अभियान' की चर्चा की है। हमारी तीसरी बार तथा नई सरकार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर्ड हुए हैं, उस हिसाब से 50,00,000 से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है। जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब-करीब सवा करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और उसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में 'ड्रोन दीदी योजना' की चर्चा हो रही है। गांवों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया है। महिला के हाथों से ड्रोन चलाते हुए देखकर, गांव के लोगों का महिलाओं को देखने का नजरिया बदल रहा है। आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर-करके लाखों रुपये कमाने लगी हैं। 'मुद्रा योजना' भी नारी शक्ति के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं ने पहली बार 'मुद्रा योजना' का लाभ लेकर उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चार करोड़ परिवारों को जो घर दिए गए हैं, उनमें से करीब-करीब 75 प्रतिशत मकान ऐसे हैं, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। यह बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि रूरल इकोनॉमी में खेती-किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के चार स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। मैं वर्ष 2014 के बाद की बात बताता हूं और यह बहुत बड़ा जम्प है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो लोग यहां किसानों की बातें करते हैं, वर्ष 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी। रात-रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। वह जमाना था, जब खाद

किसानों के नाम पर निकलती थी, लेकिन खेत में नहीं पहुंचती थी, कालेबाजारी से कहीं और ही पहुंचती थी और 1 रुपये 15 पैसे वाला हाथ की सफाई का खेल चलता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड का महासंकट आया, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दुनिया में अनाप-शनाप दाम बढ़ गए और यह परिणाम हुआ, क्योंकि हम यूरिया पर निर्भर हैं, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। आज भारत सरकार को यूरिया का एक बोरा 3,000 रुपये में पड़ता है, सरकार ने वह बोझ झेला और किसान को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दिया है। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले दस साल में 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 'पीएम किसान सम्मान निधि' से करीब साढ़े तीन लाख करोड रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में तीन गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी तीन गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन हमारे सेवाकाल के दौरान 'पीएम फसल बीमा योजना' के तहत दो लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। जो लोग संविधान की बातें करते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। यह भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पानी की योजनाओं को लेकर इतना क्लियर विज़न था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। सौ से बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, जो दशकों से लटकी हुई थीं, हमने उनको पूरा करने का अभियान चलाया, ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहेब का विज़न नदियों को जोड़ने का था। नदियों को जोड़ने की वकालत बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक, दशक के दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कई नदियों को जोड़कर जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है। हर देशवासी का एक सपना होना चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट क्यों न हो? आज मुझे खुशी होती है कि भारत की चाय के साथ-साथ हमारी कॉफी भी दुनिया में अपनी महक फैला रही है, बाजारों में धूम मचा रही है। ईवन, कोविड के बाद हमारे टर्मरिक की सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। आप जरूर देखेंगे कि आने वाले समय में हमारा प्रोसेस्ड सी-फूड और एक चीज, जिसको लेकर पता नहीं क्यों दर्द हुआ, वह बिहार का मखाना, दुनिया में पहुंचने वाला है। हमारा मोटा अनाज, यानी श्री अन्न भी दुनिया के बाजारों में भारत की शान बढ़ाएगा। विकसित भारत के लिए फ्यूचर-रेडी शहर भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमें उस दिशा में आगे काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली-यूपी को जोड़ने वाली पहली 'नमो रेल' का लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला।

ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों तक पहुंचे, यह हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दस साल में दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क डबल हुआ है और आज टियर 2 और 3 सिटी में भी मेट्रो नेटवर्क पहुंच रहा है। आज हम सभी गर्व कर सकते हैं कि आज भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर को पार कर गया है। इतना ही नहीं वर्तमान में और एक हजार किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी कई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए हैं। 12 हजार इलेक्ट्रिक बसों को हमने देश में दौड़ाना शुरू किया है। दिल्ली की भी हमने सेवा की है और दिल्ली को दिया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का समय-समय पर विस्तार होता रहता है। आज बड़े शहरों में गिग इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण एरिया डेवलप हो रहा है। लाखों युवा इसमें जुड़ रहे

हैं। हमने इस बजट में कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर ऐसे गिग वर्कर्स अपने को रजिस्टर करवाएं। उनके वेरिफिकेशन के बाद, इस न्यू एज सर्विस इकोनॉमी में, किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं, इसके लिए उनको एक आईडी कार्ड मिलेगा। हमने कहा है कि इन गिग वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इससे गिग वर्कर को स्वास्थ्य की दिशा में सहायता मिलेगी। एक अनुमान है कि आज देश में करीब-करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स हैं। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में जॉब के अवसर लेकर आता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारी नीति साफ है कि एमएसएमई को सरलता, सहुलियत और संवर्धन मिले। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। इस बार हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया है। एक मिशन मोड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब एमएसएमई सेक्टर को बल देना और एमएसएमई के माध्यम से अनेक नौजवानों को रोजगार देना, स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऐसे पूरे इको सिस्टम को हम बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए कई पहलुओं पर हमने काम शुरू किया है। एमएसएमई के लिए क्राइटेरिया वर्ष 2006 में बनाया गया था। उसे अपडेट नहीं किया गया। पिछले दस वर्षों में इस क्राइटेरिया में हमने दो बार अपग्रडेशन करने का प्रयास किया और इस बार हमने एक बहुत बड़ा जम्प लगाया है। पहली बार वर्ष 2020 में, दूसरी बार इस बजट में हमने एमएसएमईज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर तरफ उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। एमएसएमईज़ के सामने चुनौती फार्मल फाइनैंशियल रिसार्सेस की कमी की रही है। कोविड के संकट के काल में एमएसएमईज़ पर विशेष बल दिया गया। हमने खिलौना उद्योग पर विशेष बल दिया। हमने कपड़ा उद्योग पर विशेष बल दिया।

हमने उनको कैश फ्लो की कमी नहीं होने दी और बिना किसी गारंटी पर लोन दिया। हजारों उद्योगों में लाखों नौकरियों की संभावनाएं बनीं और नौकरियां सुरक्षित भी हुईं। छोटे उद्योग, उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट गारंटी कवरेज, उस दिशा में हमने कदम उठाए, जिसके कारण ईज

ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिला और गैर जरूरी नियमों को कम करने के कारण उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड रहता था, उनको एकाध व्यक्ति को काम के लिए पैसे देने पड़ते थे, वह भी बंद कर दिया गया।

एमएसएमईज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने जो नई नीतियां बनाई हैं, आपको खुशी होगी, एक समय था, वर्ष 2014 के पहले खिलौने जैसी चीजें हम इम्पोर्ट करते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239 परसेंट वृद्धि हुई है। एमएसएमईज़ के जरिए संचालित ऐसे कई सेक्टर्स हैं, जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। मेड इन इंडिया कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स के सामान आज दूसरे देशों के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना, यह कोई सरकारी सपना नहीं होता है। यह 140 करोड़ देशवासियों का सपना है और इस सपने को हम सब जितनी ऊर्जा दे सकते हैं, देने का प्रयास करना है। दुनिया में उदाहरण है, 20-25 साल के कालखण्ड में दुनिया के कई देशों ने विकसित बनकर के दिखाया है तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डिमांड है। हम क्यों नहीं कर सकते? इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और हम भी 2047, जब देश आजाद होने के 100 साल होंगे, तब हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। यह सपना लेकर के चलना चाहिए। मैं विश्वास से कहता हूँ कि हमें और बड़े लक्ष्य पार करने हैं और हम करके रहेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूँ। सभी नेताओं से आग्रह करता हूँ, देशवासियों से आग्रह करता हूँ। अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी, अपने-अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हम सबके लिए देश सर्वोपरी है और हम

मिलकर के विकसित भारत के सपने को अपना, 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी अपना सपना माना है, इस सपने को लेकर के चल पड़े। देश विकसित होगा। हमारे बाद की जो पीढ़ियां होंगी, वे कहेंगी कि 2025 में एक संसद ऐसी थी, जहां बैठा हुआ हर सांसद विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका भी आभार करता हूँ, सदन का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री अमरा राम जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री सुधाकर सिंह जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल एवं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के सामने मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

18.41 hrs

At this stage, Shri Akhilesh Yadav and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं।"